सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र में

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, सोमवार, 14 मार्च, 2011 (फाल्गुन 23, शक सम्वत्, 1932)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा के माननीय सदस्यगण;

मैं आप सभी महानुभावों का वर्ष 2011 में विधानसभा के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ और देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिये जा रहे सहयोग के लिए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता की वर्ष 2011 में समृद्धि एवं खुशहाली की भी कामना करती हूँ। मुझे आशा है कि नव वर्ष हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा और प्रतिबद्धता प्रदान करेगा ताकि हम प्रदेश और प्रदेशवासियों की सेवा कर सकें।

(2) मेरी सरकार ने–

- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन किये जाने के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों को दूर किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों की सेवायोजन नियमावली प्रख्यापित कर दी है।
- सेवाकाल के दौरान लापता सरकारी सेवकों जिन्हें लापता होने के 07 वर्ष बाद मृत्युकल्पित किया गया हो, के आश्रितों को भी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन के प्राविधान किये जाने के लिए मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में संशोधन कर अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2010 द्वारा संशोधन नियमावली प्रख्यापित कर दी है।
- राज्याधीन सेवाओं में समूह क,ख,ग एवं घ के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों पर कार्यवाही से पूर्व शिकायतों की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये हैं।
- लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु कोई अधिकृत चयन संस्था न होने के कारण रिक्त पदों पर चयन में हो रही कठिनाईयों को दूर किये जाने के लिए उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को चयन संस्था नामित कर दिया है।
- समूह ग के पदों पर राज्य के नागरिकों को भर्ती के अवसर प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा आयोग

की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली निर्गत कर दी है जिसके द्वारा समूह 'ग' पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता तथा अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय अर्हता के रूप में सम्मिलित किया गया है।

- लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के लगभग 12000 पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् के द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।
- राज्याधीन सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर सीधी भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही समयबद्ध रूप से करने के निर्देश निर्गत कर दिये हैं।
- निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं समूह ग के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत कर दिये हैं।
- राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लगभग 18000 रिक्त पदों जिन्हें पोषक संवर्ग में निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा था, पर पदोन्नति किये जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

(3) **उत्तराखण्ड अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं** की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटना मेरी सरकार के लिए अत्यंत चुनौती पूर्ण कार्य रहा है, तथापि ऐसे संकट के समय राज्य की जनता को कम से कम कठिनाई हो, इसके लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार ने–

- भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप कदाचित भारत में पहली बार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, समस्त जनपदों में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, जनपद आपदा प्रतिक्रिया निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि एवं जनपद आपदा न्यूनीकरण निधियों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य आपदा सलाहकार समिति का भी गठन कर दिया है।
- आपदा की स्थिति में प्रतिवादन हेतु उत्तरदायी प्रमुख विभागों के विषय में मानक परिचालन कार्य विधियाँ {Standard Operating Procedures (SOPs)} तैयार की गयी हैं। साथ ही, राज्य आपदा प्रबंधन कार्य योजना भी तैयार कराई जा रही है जिससे आपदाओं के समय बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सके तथा सभी विभागों को अपने उत्तरदायित्व की पूर्ण जानकारी हो। इसके अतिरिक्त नीति विषयक निर्णयों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गतिशील किया जा रहा है। प्रत्येक जिले एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक समय एवं प्रत्येक दिन संचालित होने वाले जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का रख–रखाव भी किया जाना प्रस्तावित किया है।
- भूकम्प जनित आपदा के प्रबंधन एवं उसके न्यूनीकरण के लिए छः शहरों का भूकम्प जोखिम आंकलन का कार्य कराया है। इसके आधार पर इन शहरों के लिए विस्तृत नियोजन में मदद मिलेगी। राज्य के समस्त जनपदों में भूकम्प अवरोधी प्रदर्शन इकाईयों का निर्माण कर रही है। इसके अतिरिक्त भू स्खलन, बादल फटना, बाढ एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की जोखिम के आंकलन/अध्ययन भी कराये जाने प्रस्तावित हैं। स्थानीय जनता की क्षमता वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर चिन्हित अटल आदर्श ग्राम में खोज एवं बचाव प्रशिक्षण प्रारम्भ कर रही है, जिससे ग्राम स्तर पर खोज एवं बचाव दल गठित किये

जा सकें तथा उन्हें समुचित उपकरण उपलब्ध कराकर आपदा के समय प्रथम प्रतिवादन दल के रूप में उपयोग में लाया जा सके।

- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मौसम की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे समय रहते क्षेत्र के निवासियों को सम्भावित आपदा के लिए तैयार रहने एवं यथासमय बचाव के उपाय किये जा सकें। मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को एक डाप्लर रडार की स्थापना हेतु चयनित किया गया है। इस संबंध में मसूरी एवं नैनीताल में उपयुक्त भूमि की चयन की कार्यवाही गतिमान है। इस रडार की स्थापना से मौसम का पूर्वानुमान लगाने में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त बेहतर संचार व्यवस्था हेतु मेरी सरकार द्वारा एन.आई.सी. के वी–सैट द्वारा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को सभी जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है। उपग्रह संचार आधारित वी–सैट प्रणाली से गृह मंत्रालय, मौसम भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा देश के 22 मल्टी हैजार्ड राज्यों से जोड़ दिया है।

- इस वर्ष अतिवृष्टि से अत्यंत भीषण आपदा का सामना राज्य को करना पड़ा जिसमें लगभग दो सौ से अधिक मानव जीवन की क्षति हुई तथा साठ हजार से अधिक आवासीय इकाईयां नष्ट हुई। भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से आपदा का प्रतिवादन अत्यंत तीव्रता से एवं सफलता से किया। अब यह भी निरंतर प्रयास कर रही है कि पुनर्निर्माण व मरम्मत के कार्य पूर्ण पारदर्शिता से एवं समयबद्ध आधार पर पूरे हो जायं। सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों को शीघ्र सहायता दिये जाने हेतु मेरी सरकार ने अनवरत रूप से प्रयास किये हैं।

(4) **प्रदेश के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के** वित्तीय संसाधनों एवं रोजगार के अवसरों के सृजन के लिये मेरी सरकार द्वारा राज्य में पूंजी निवेश के लिये बेहतर वातावरण सृजित किये जाने एवं अवस्थापना सुविधाओं के लगातार सुदृढीकरण को प्राथमिकता दी है। उद्यमियों एवं उद्यमी

संघों के साथ निरन्तर संवाद स्थापित कर तथा जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के माध्यम से उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सकारात्मक कार्यवाही की गई है। **एकल खिड़की सूचना, सम्पर्क एवं सुगमता व्यवस्था** को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं। राज्य में स्थापित उद्यमों द्वारा राज्य के औद्योगिक वातावरण को उपयुक्त पाया गया है और अधिकतर इकाईयों द्वारा यहाँ लगातार विस्तारीकरण किया जा रहा है। विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत राज्य में अगस्त, 2010 तक लगभग ढाई हजार औद्योगिक इकाईयाँ उत्पादन में आई हैं, जिनमें छब्बीस हजार पांच सौ करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। उद्योग क्षेत्र में गत वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है एवं मेरी सरकार उच्च विकास दर प्राप्त करने में सफल रही है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने की दृष्टि से स्वीकृत विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अनुकूल परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस नीति के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2010 तक पर्वतीय क्षेत्रों में कुल एक हजार सात सौ पचास सूक्ष्म व लघु उद्यमों की स्थापना की गई है, जिनमें लगभग दो सौ करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा छः हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रस्तावित निवेश के आंकड़ों के विश्लेषण से इन क्षेत्रों में स्थानीय एवं अन्य उद्यमियों का सकारात्मक रुझान परिलक्षित होता है।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में जिला उद्योग केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत सरकार द्वारा भी जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ कर स्वरोजगार एवं निवेश प्रोत्साहन की ओर बल दिया गया है। मेरी सरकार ने सभी जिला उद्योग केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया है और इनमें स्थापित परामर्श कक्ष के माध्यम से नव उद्यमियों एवं शिक्षित युवाओं को उद्यम स्थापना हेतु समुचित सूचनायें, जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है। इन्टरनेट के अधिकतम उपयोग से सूचनाओं के आदान–प्रदान, जिला उद्योग

केन्द्रों एवं निदेशालय के बीच ऑन लाइन संवाद का लाभ लिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु इकाईयों की सुविधा के दृष्टिगत उद्यमी इच्छा पत्र (इण्टरप्रिन्यौर्स मैमोरेण्डम) भाग–1 ऑन लाइन फाइल किये जाने की व्यवस्था की गई है।

रुड़की में ड्रॉईंग एवं सर्वेईंग इन्स्ट्रूमेन्ट कलस्टर के विकास एवं आधुनिकीकरण की परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इस परियोजना में अत्याधुनिक सामूहिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा सकेगी।

राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को विपणन, प्रोत्साहन हेतु उद्योग निदेशालय, देहरादून में तथा राज्य के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ''हिमाद्रि'' इम्पोरियम स्थापित किये गये हैं, जिनमें राज्य के शिल्प उत्पाद उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में ''भीकाजी कामा प्लेस'' तथा ''बाबा खड़ग सिंह मार्ग'' में स्थापित ''हिमाद्रि'' शो–रूम के नियमित संचालन की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है। शिल्प उत्पादों एवं हथकरघा उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन के लिये हैण्डलूम एक्सपो तथा क्राफ्ट बाजार के आयोजन नियमित रूप से किये जा रहे हैं। हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर गाँधी शिल्प बाजार एवं विशेष हैण्डलूम एक्सपो के आयोजन किये गये।

दिनांक 14–27 नवम्बर, 2010 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में **भारत** अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2010 में राज्य द्वारा प्रतिभाग किया गया है। मेले में उत्तराखण्ड राज्य के हथकरघा व हस्तशिल्प बुनकरों तथा राज्य की औद्योगिक इकाईयों के स्टॉल लगाये गये हैं। राज्य के पर्यटन, कृषि, उद्यान, फल संरक्षण, ऑर्गेनिक बोर्ड, सीड बोर्ड, उरेडा, बम्बू बोर्ड एवं यूएचएचडीसी द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत विपणन व प्रदर्शन किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत हथकरघा विकास योजनान्तर्गत छिनका (चमोली), मंगलौर (हरिद्वार), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुनस्यारी, धारचूला (पिथौरागढ़) तथा कालसी (देहरादून) में छः हथकरघा कलस्टरों को विकसित किया जा रहा है।

हिमालयी क्षेत्रों में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत खनिजों का वैज्ञानिक दृष्टि से विदोहन किया जा रहा है।

(5) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान जहाँ एक ओर राज्य की लोक–भाषाओं व बोलियों के संरक्षण में कार्य करेगा, वहीं दूसरी ओर विश्व के अनेकानेक भाषाओं के अध्ययन केन्द्रों को भी स्थापित करेगा। विश्व की भाषाओं के अध्ययन से युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में मेरी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। पर्यटन, व्यापार, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवकों को प्रोत्साहन देना भी मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में है। उत्तराखण्ड की भाषाओं के सर्वेक्षण करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मेरी सरकार की उत्तराखण्ड के किसी एक गाँव को साहित्य–ग्राम के रूप में स्थापित करने की योजना है, इसके साथ ही उत्तराखण्ड की लोक भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु भी मेरी सरकार प्रयासरत है।

यह हर्ष का विषय है कि हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठतम साहित्यकारों की जन्मभूमि उत्तराखण्ड है। मौलाराम से लेकर सुमित्रानन्दन पंत, चन्द्रकुँवर बड़थ्वाल, शैलेश मटियानी, डॉ0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने इस पवित्र भूमि में जन्म लिया है। हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए मेरी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन, पाण्डुलिपियों का संरक्षण एवं हिन्दी साहित्यकारों को सम्मान प्रदान करने का कार्य करेगी। मेरी सरकार द्वारा हिन्दी की उन्नति के लिए समय–समय पर संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे तथा हिन्दी वाङमय के शब्दकोष के विस्तार के लिए तकनीकी विद्वानों की कार्यशालायें आयोजित कर शब्दकोष तैयार करके सॉफ्टवेयर तैयार किये जाने का भी प्रस्ताव है।

संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाये जाने के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार आगामी योजना में प्रदेश के एक लाख छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षित एवं उनका सम्मेलन कराना, त्रिदिवसीय विश्वस्तरीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन, विभिन्न भाषाओं में विद्यमान साहित्य का संस्कृत में अनुवाद कर पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाना, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, प्रदेश के हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक एवं पी.एच.डी. आदि विभिन्न स्तरों पर संस्कृत

विषय से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के कार्य कर रही है।

(6) **उत्तराखण्ड 15 मई 2008 को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय देव भूमि–108 आपातकालीन सेवा प्रारम्भ करने वाला प्रथम हिमालयी राज्य एवं उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है**, हमारी पुरजोर कोशिश थी कि राज्य का कोई भी नागरिक जरूरी चिकित्सा सुविधा से वंचित न रह जाए, **108 आपातकालीन सेवा** इस मिशन में **'संजीवनी'** साबित हुई है।

उत्तराखण्ड राज्य में **संजीवनी, संकटमोचन** और **जीवनदायनी** जैसे विभिन्न नामों से लोकप्रिय **आपातकालीन 108 सेवा** को अब राज्य महिला आयोग, पुलिस और वन विभाग से भी जोड़ दिया गया है। **आपातकालीन 108 सेवा** की चलती एम्बुलेंस में अब तक **2130** बच्चों का जन्म हुआ है। जो एक विश्व कीर्तिमान है। अब तक कुल ढाई लाख आकस्मिक घटनाओं में 108 अपनी सेवा प्रदान कर चुका है।

'मिशन सड़क दुर्घटना' में यह सेवा एक देवदूत की तरह काम कर रही है। इस सेवा के माध्यम से गंभीर रूप से घायलों को त्वरित चिकित्सा मुहैय्या कराकर उनके प्राणों की रक्षा की गई है। कम समयावधि में ही इस सेवा द्वारा आपातकालीन स्थिति में लगभग सवा दो लाख से अधिक लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर राज्य के दुर्गम से दुर्गम और अन्तिम सीमावर्ती गांव तक भी चिकित्सा सुविधा पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है।

हमारी सरकार भविष्य में **'जल' और 'आकाश'** में भी इस योजना को लागू करने जा रही है। इस क्रम में हमने टिहरी बाँध में एक बोट एम्बुलेंस का संचालन प्रारम्भ कर दिया है और शीघ्र ही सरकार एक बोट एम्बुलेंस का संचालन वहाँ करने जा रही है।

अभी तक आपातकालीन–108 सेवा पीड़ितों को निकट चिकित्सा केन्द्र तक पहुँचाने तथा उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का कार्य करती थी, निकट भविष्य में हम इलाज के पश्चात् स्वस्थ हुए व्यक्ति को उसके घर तक

पहुँचाने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य हेतु हमने अब 108 सेवा को मुख्यमंत्री सुदूरवर्ती स्वास्थ्य रक्षक योजना से भी जोड़ दिया है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी तथा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखण्ड के मेधावी एवं गरीब छात्रों के साथ समस्त प्रवेशित छात्रों को न्यूनतम फीस पर एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सुविधा मेरी सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

मेरी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध पत्र भरवा रही है, ताकि पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त निकलने वाले प्रत्येक बैच को इन क्षेत्रों में पांच वर्ष के लिए तैनात किया जा सके।

उत्तराखण्ड में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को संचालित करने एवं इसमें प्रवेशित छात्र–छात्राओं को देश के अन्य भागों में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने की अच्छी संभावनायें विद्यमान हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् का गठन किया जा रहा है, ताकि पैरामेडिकल स्नातक की पंजीकरण सुविधा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के सर्वोत्तम अवसर भी उपलब्ध कराये जा सकें।

मेरी सरकार द्वारा एम्स ऋषिकेश की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। समस्त वांछित आवश्यक सुविधाओं को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया गया है तथा भविष्य में एम्स की स्थापना होने एवं संचालन के उपरान्त वांछित अन्य सुविधाओं को भी चरणबद्ध रूप से पूरा प्रयास किया जायेगा।

मेरी सरकार ने प्रथम राजकीय नर्सिंग कालेज के रूप में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून की स्थापना की गई। भविष्य में इसको सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये आयु–सीमा 50 वर्ष तक के 227 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नियुक्त किया है।

मेरी सरकार जनपद हरिद्वार के भगवानपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अधिग्रहण करते हुए राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने जा रही है।

मेरी सरकार द्वारा महर्षि चरक की जन्मभूमि चरेख डाण्डा में अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार ने जनपद नैनीताल के भवाली सेनोटोरियम में प्रथम आयुष ग्राम पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित किये जाने हेतु मैसर्स इमामी लिमिटेड कलकत्ता से अनुबन्ध निष्पादित कर दिया है।

मेरी सरकार ने होम्योपैथिक चिकित्सा की ओर, आम जनता का रूझान बढ़ाने के फलस्वरूप राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जनपद बागेश्वर, चम्पावत एवं रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल परिसर में, मा0 उच्च न्यायालय में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, जनजाति क्षेत्र, हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सालयों की स्थापना करके जनहित में एक छत के नीचे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सा सुलभ कराई है।

इसके अतिरिक्त–

- श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना,
- होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त 70 पदों पर शीघ्र नियुक्ति किया जाना;
- केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रम के तहत 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना के साथ ही कार्मिकों की तैनाती किया जाने का कार्य मेरी सरकार द्वारा तत्परता से किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को आधुनिक सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने हेतु प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर एवं तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किये जाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में मेरी सरकार राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक/दैवीय

आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जनसामान्य को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ मोबाईल चिकित्सालयों का संचालन तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना का क्रियान्वयन भी कर रही है।

मेरी सरकार ने–

- दून चिकित्सालय, देहरादून में रोगियों की निरन्तर वृद्धि एवं शैय्या उपयोगिता दर में वृद्धि के दृष्टिगत चिकित्सालय का उच्चीकरण करते हुए 150 अतिरिक्त शैय्यायुक्त भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया है।
- जिला चिकित्सालय, चम्पावत में चिकित्सालय को क्रियाशील कर रही है।
- बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का निर्माण तथा बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय, नैनीताल का पुनर्निर्माण कार्य भी कर रही है।
- ग्रामीण/पर्वतीय क्षेत्रों में द्वितीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं हेतु आगामी वर्ष में चार नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
- जनपद देहरादून में आधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधा हेतु महात्मा गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र का भवन निर्माण कार्य करा रही है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून में डॉयलिसिस सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नैफ्रोलॉजी यूनिट क्रियाशील कर दी गयी है, साथ ही रुड़की सहित कार्डियोलॉजी सेन्टर की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- राज्य कर्मचारियों/पेन्शनरों को नगद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु हैल्थ स्मार्ट कार्ड योजना आरम्भ कर दी गयी है।
- राज्य के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गयी है।
- बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट स्थापित कर रही है।

- ए0डी0बी0 (एशियन डेवलपमेंट बैंक) के सहयोग से कोटद्वार तथा पिथौरागढ में डायगोनास्टिक सेंटर की स्थापना की कार्यवाही ,कर रही है।
- आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में दन्त विकारों के उपचार हेतु उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा में सचल वाहन सेवा शुरु कर रही है।
- चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालयों को पी0पी0पी0 मोड में संचालित किये जाने की दिशा में कार्यवाही कर रही है।
- दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत एयर एम्बुलेन्स आपातकालीन सेवा एवं बोट एम्बुलेन्स आपातकालीन सेवा प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही कर रही है।
- चिकित्सकों की कमी को दूर कर रही है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों / यात्रा मार्गों पर चरणबद्ध रूप से ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना कर रही है।
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।
- एच0आई0वी0 / एड्स की जानकारी, परामर्श व परीक्षण की निःशुल्क सुविधा, एच0आई0वी0 / एड्स रोगियों के उपचार हेतु औषधि की उपलब्धता, एच0आई0वी0 मुक्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नार्को द्वारा उपलब्ध करायी गयी ब्लड डोनेशन वैन में ब्लड लिये जाने एवं ब्लड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कर रही है।
- एकीकृत रोग निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है।
- जननी सुरक्षा योजना तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित कर रही है।

(7) **विभिन्न जनपदों में स्थापित जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के** माध्यम से मेरी सरकार अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का वितरण कर रही है और प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ऋण वितरण, खाद,

बीज वितरण, कीटनाशक रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को कराई जा रही है।

(8) **मेरी सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से बेसिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन** योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, मकतब, मदरसों राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही है।

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

मलिन बस्तियों के कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, सपेरे, अनाथ, अतिनिर्धन, घुमन्तू जैसे शहरी अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु वाउचर आधारित पहल कार्यक्रम का संचालन भी मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं को सुगठित किये जाने हेतु राजकीय जूनियर हाई स्कूल एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं के आकार एवं राज्य की आवश्यकता के अनुरूप अनुभागों के मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है।

राजकीय विद्यालयों को भौतिक एवं शैक्षिक रूप से उत्कृष्ट बनाये जाने हेतु जिला मुख्यालय के राजकीय इण्टर कॉलेज को आदर्श विद्यालय में परिणित करने का निर्णय लेते हुए मेरी सरकार ने शैक्षिक तकनीकी में इन्फॉरमेशन तकनीकी को सम्मिलित कर कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 500 विद्यालयों में स्मार्ट स्कूल बनाने हेतु पी0पी0पी0 मोड में संचालित किये जाने के लिए भारत सरकार से सैद्धान्तिक सहमति भी प्राप्त कर ली है।

बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर एक हजार रुपये तथा कक्षा 10 में प्रवेश पर दो हजार रुपये की तेजस्वी छात्रवृत्ति तथा उत्तराखण्ड के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों के उत्तराखण्ड

मूल के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था मेरी सरकार द्वारा की गयी है एवं माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा तीन हजार रुपये की धनराशि बचत पत्र के रूप में दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालयों को दीन दयाल उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पाँच जनपदों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों का संचालन आरम्भ किया गया है। इन विद्यालयों में पचास प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की बालिकाओं की कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की बालिकाओं की निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा इन बालिकाओं को कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु इस योजना का विस्तारीकरण किया गया है।

मेरी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरु कर दिया है और इस अभियान के सफल संचालन के लिए माध्यमिक विद्यालयों में मानकानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, पेयजल एवं शौचालय आदि सुविधाएं विद्यालयों को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

मेरी सरकार द्वारा–

- नदियों के खनन, वन एवं ईंट भट्टों में कार्य करने वाले सीजनल मजदूरों हेतु **"देव भूमि मुस्कान योजना"** संचालित कर रही है।
- सभी वर्गों की कक्षा 8 तक पढ़ने वाली छात्राएं/बी0पी0एल0 छात्र/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को फ्री ड्रैस वितरित की जा रही है।
- गरीब मेधावी छात्र–छात्राओं को मेडिकल/इन्जीनियरिंग कोचिंग हेतु पी0पी0पी0 मोड में फ्री कोचिंग/काउन्सलिंग सेन्टर चलाये जा रहे हैं।

- अध्ययन से वंचित बच्चों हेतु सपनों की उडान के तहत मोबाईल स्कूल चलाये जा रहे हैं।
- बेसिक शिक्षा निदेशालय के गठन का निर्णय लिया गया है।
- उच्च शिक्षा में सेट (SET) राज्य पात्रता परीक्षा का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय, मजरा महादेव, तहसील थलीसैंण (पौड़ी) में एक नए महाविद्यालय की स्थापना की है।

इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के क्रम में राजकीय महाविद्यालय, लोहाघाट एवं उत्तरकाशी को एन0सी0टी0ई0, जयपुर से एल0ओ0पी0 निर्गत होने के उपरान्त स्ववित्त पोषित बी0एड0 कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी है और डोईवाला, स्याल्दे तथा मानीला में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय खोल कर अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

मेरी सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग से जोड़ने हेतु प्रथम चरण में 25 राजकीय महाविद्यालयों को एवं द्वितीय चरण में 14 राजकीय महाविद्यालयों तथा 13 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को चयनित किये जाने की महत्वाकांक्षी योजना को प्रारम्भ किया है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को एडूसेट के माध्यम से सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु मेरी सरकार ने उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून के सहयोग से प्रदेश में 25 राजकीय महाविद्यालयों में एडूसेट कार्यक्रम के क्रियान्वयन किये जाने की प्रक्रिया चलाई है।

एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) में वर्तमान शैक्षिक सत्र से स्ववित्त पोषित आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है।

मेरी सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अकादमिक स्टॉफ कॉलेज खुलवाने में सफल रही है। इससे युवाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रगति के और अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

मेरी सरकार–

- आगामी तीन वर्षों में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की सभी कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने;
- सैण्टर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन ट्रांस हिमालयन हिस्ट्री एण्ड कल्चर एण्ड हिस्ट्री ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की स्थापना करने;
- यूनिवर्सिटी इन्फोर्मेशन मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना करने; तथा
- एस0सी0 / एस0टी0 / निर्धन वर्ग के छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए संकल्पबद्ध है;

मेरी सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 164 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना किये जाने के साथ–साथ 11 संस्थाओं से विभिन्न रोजगारपरक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक गठजोड (एम0ओ0यू0) निष्पादित करने में सफल रही है। अध्ययन केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं विश्वविद्यालय तथा अध्ययन केन्द्रों के बीच सुगम समन्वय हेतु आठ क्षेत्रीय कार्यालयों की भी स्थापना इसी वर्ष की गयी।

मेरी सरकार–

- दून विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रबन्धन में पी0जी0 डिप्लोमा प्रारम्भ करने;
- दून विश्वविद्यालय में इस सत्र से तीन और नये स्कूल प्रारम्भ करने;
- प्रदेश के नवयुवकों को विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी (उजाला), भवाली, जनपद नैनीताल में एक उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की है; तथा
- इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जनपद टिहरी गढ़वाल के बादशाही थौल नामक स्थान पर तथा वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थापित किए जाने का निर्णय ले लिया है।

मेरी सरकार के अथक प्रयास से तथा भारत सरकार के सहयोग से जनपद पिथौरागढ़ में गणाई गंगोली, कनालीछीना एवं डीडीहाट स्थानों पर समेकित पॉलिटेक्निक का विकास किया जा रहा है।

मेरी सरकार छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में मेरी सरकार ने राज्य के प्रथम महिला तकनीकी महाविद्यालय के रूप में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, सुद्धोवाला को विकसित करने का संकल्प लिया है।

देववाणी संस्कृत के उत्थान और विशेष दर्जा दिये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया है। वर्तमान में राज्य में चौरासी संस्कृत शिक्षा केन्द्र संचालित है। जिसमें 47 महाविद्यालय है। इन विद्यालय/महाविद्यालयों का संचालन एवं विकास के दृष्टिकोण से वर्तमान में अनेक कार्यक्रम जैसे–
शिक्षक पुरस्कार, अध्यापकों की नियुक्ति एवं भर्ती प्रक्रिया, संस्कृत विद्यालयों को अनुदान, संस्कृत ग्राम एवं संस्कृत नगर, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का प्रयास, निःशुल्क एवं आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाने पर विचार आदि संचालित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में मेरी सरकार संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय में पर्यटन एवं तीर्थाटन में पी0जी0 डिप्लोमा, पुराण–कथा तथा प्रवचन में पी0जी0 डिप्लोमा तथा भक्ति संगीत में पी0जी0 डिप्लोमा संचालित कर रही है।

(9) मेरी सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण/वन संरक्षण की दिशा में किए गए सराहनीय कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा इस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा है, जो प्रदेश के लिये गौरव का विषय है।

मेरी सरकार 14 नई योजनायें जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड हरित विकास योजना, मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना तथा मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना सम्मिलित है, में शीघ्रता से कार्य कर रही है।

मेरी सरकार ने प्रदेश में रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाओं जैसे बांस एवं रिंगाल, च्यूरा, चूक थुनेर एवं अन्य मेडिसनल आदि प्रजातियों का वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण के साथ–साथ रोजगार के अवसर बढ़ाये हैं।

मेरी सरकार की जीव संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों के फलस्वरूप विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट लैण्ड स्केप विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व के रूप में उभर कर आया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार इस भूखण्ड में औसतन 8.5 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ की उपस्थिति दर्ज की गयी, जो एक कीर्तिमान है।

मेरी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु पहल की है और मेरी सरकार ने–

- कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को 'कॉर्बेट टाइगर रिजर्व' अधिसूचित किया है,
- 'स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स' के गठन संबंधी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं,
- 'कॉर्बेट टाइगर कन्जर्वेशन फाऊंडेशन' का गठन किया गया है।

(10) मेरी सरकार ने सेब फसल बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सेब उत्पादक क्षेत्रों के कृषकों/उद्यानपतियों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 के द्वारा मौसम आधारित सेब/आम फसल बीमा योजना लागू की गई है।

वाणिज्यिकी औद्यानिकी विकास को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार के सहयोग से मेरी सरकार ने कृषकों/उद्यमियों को मैचिंग ग्रान्ट उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की है।

राज्य में पुष्प विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार द्वारा पहल कर लगभग तेरह सौ हेक्टेयर में पुष्पों की खेती की जा रही है।

मेरी सरकार ने औद्यानिकी निवेशों के मूल्य निर्धारण व गुणवत्ता परीक्षण में राज्य के प्रगतिशील कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया है

तथा 50 प्रतिशत अनुदान पर छोटे पॉलिहाऊस द्वारा बेमौसमी सब्जी/पुष्प उत्पादन द्वारा कृषकों की आय बढ़ाने की मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना प्रारम्भ की है।

मेरी सरकार ने रेशम के उत्पादों के मूल्य सम्वर्द्धन, विपणन आदि कोसोत्तर गतिविधियों के विकास हेतु सिल्क पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। सिल्क पार्क के अंतर्गत समस्त विभागीय गतिविधियों का संजीव प्रदर्शन एवं अध्ययन की व्यवस्था है, जिससे समस्त प्रदेश के रेशम उत्पादन एवं बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

भारत सरकार के सहयोग से मेरी सरकार वर्तमान में दस रेशम कलस्टर्स का विकास कर रही है। इन कलस्टर्स में कृषकों/लाभार्थियों को रेशम कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति, विशुद्धिकरण सामग्री तथा कीटपालन कक्ष के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

चाय उत्पादन से वर्तमान में 1270 काश्तकारों के परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि चाय उत्पादन कार्यक्रम में 55 प्रतिशत की भागीदारी महिलाओं की है।

मेरी सरकार हर्बल विकास के लिए संकल्पबद्ध है और इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है।

(11) केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अर्न्तगत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण अकुशल श्रमिकों हेतु महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तथा ग्रामीण आवास हेतु इन्दिरा आवास योजना एवं ग्रामीण संयोजकता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने के साथ-साथ मेरी सरकार द्वारा भी ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना, नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री शिल्प विकास योजना, एवं न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम पर विभागीय योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करते हुए अटल आदर्श ग्राम योजना का

क्रियान्वयन मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु एक सराहनीय कदम उठाया है।

मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए अटल आवास योजना चलाई है।

मेरी सरकार ने जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के सत्रह विकास खण्डों के लगभग तैंतालिस हजार अति निर्धन परिवारों की आजीविका संवर्द्धन हेतु वाह्य सहायतित परियोजना "हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना" प्रारम्भ की है।

(12) मेरी सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से विधि सम्मत कानून व्यवस्था को बनाए रखने, सामयिक घटित अपराधों के अन्वेषण व नियंत्रण तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने, पर्यावरण एवं मानवाधिकारों के संरक्षण तथा जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में विधि के प्रति सम्मान स्थापित कर अपराधियों एवं अपराधों के नियन्त्रण व निवारण हेतु सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सफल रही है।

दशक के विश्वप्रसिद्ध प्रथम महाकुम्भ–2010 में विश्व एवं राष्ट्र के लगभग 09 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न पर्वों पर स्नान कर पुण्य अर्जित किया गया, जिसमें प्रदेश के पुलिस बल ने अन्य प्रदेशों के पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के साथ समन्वय कर सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए विश्वविख्यात महाकुम्भ को सकुशल, सुरक्षित, निर्विघ्न एवं निर्विवाद सम्पन्न कराया।

मेरी सरकार द्वारा विभिन्न अपराधों पर नियंत्रण एवं कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरन्तर चौकसी हेतु प्रभावी पैरवी की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों, सैनिक प्रतिष्ठानों, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्रमुख पर्यटन स्थलों की सुरक्षात्मक संवेदनशीलता के दृष्टिगत् प्रदेश में समुचित पुलिस बल गठित किया गया है। सार्वजनिक संस्थानों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों, जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की

गयी है। आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियों से निपटने हेतु राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ता तथा प्रत्येक जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन किया गया है। पुलिस बल की क्षमता, अनुशासन एवं आधुनिक विश्लेषणात्मक पद्धतियों में अभिवृद्धि हेतु नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गयी है।

आपराधिक मामलों में अपराधों के त्वरित निस्तारण एवं विश्लेषण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, शीघ्र न्याय दिये जाने एवं विभिन्न न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित किये जाने हेतु अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना की गयी है तथा प्रदेश में अभिसूचना तंत्र एवं आपात सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है।

टनकपुर में फायर स्टेशन की स्थापना की गयी है। अपराधों के अनावरण एवं सूचनाओं के संकलन हेतु प्रदेश में अभिसूचना केन्द्र विकसित किये गये हैं।

प्रदेश में भीड़ एवं यातायात नियंत्रण हेतु उत्कृष्ट संचार व्यवस्था वीडियो सर्विलांस प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है।

प्रदेश के पुलिस बल के अनुषांगिक होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को भी सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसमें होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याणार्थ, कल्याणकोष की स्थापना की गयी है, जिससे स्वयंसेवकों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं अनुदान दिया जाता है।

मेरी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों के सम्मान एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिमाह पेंशन, चिकित्सा सुविधा, सेवायोजन, अनुग्रह धनराशि के अतिरिक्त निःशक्त विकलांग (Bed ridden) आंदोलनकारियों के लिए दस हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन अनुमन्य की गयी है। प्रदेश में जिला कारागारों की स्थापना कारागारों में बन्दियों के भोजन, चिकित्सा, स्वच्छता एवं ,उनके मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति मेरी सरकार अत्यन्त संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों एवं उनके आश्रितों को समुचित सुविधायें एवं सम्मान की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के

महंगाई भत्ते में वृद्धि आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधायें, राजकीय एवं सार्वजनिक समारोहों में सम्मानित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण्ण गतवर्ष अनेक प्राकृतिक आपदाओं यथा अतिवृष्टि, बादल फटने एवं भू–स्खलन की समस्याओं से अपूर्णीय जन एवं धन क्षति हुई है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में प्रदेश के पुलिस बल द्वारा यथोचित सहयोग प्रदान किया गया।

(13) मेरी सरकार ने राज्य की प्राथमिकता के कार्यक्रमों तथा समय–समय पर की जाने वाली जनोपयोगी घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की स्थापना की है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार जन हितकारी महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन तथा नियमित रूप से अनुश्रवण किये जाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है।

(14) मेरी सरकार अटल आदर्श खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध खाद्यांन्न को दो रुपये किलो गेहूँ व तीन रुपये किलो चावल, प्रति किलो की दर से उपलब्ध करायेगी।

मेरी सरकार गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले परिवारों को चार रुपये किलो गेहूँ तथा छः रुपये किलो चावल, प्रति किलो की दर से उपलब्ध करायेगी।

मेरी सरकार गेहूँ, धान तथा चावल की खरीद में अग्रणी रही है और विधिक माप के क्षेत्र में चहुंमुखी प्रगति की है।

(15) राज्य में कृषि उत्पादन में विकास की संभावनाओं को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने का दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया है, जिसे वर्तमान वर्ष से मुख्यमंत्री खाद्य. सुरक्षा मिशन के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में उपलंब्ध एक लाख हेक्टेयर कृषि योग्य परती भूमि को क्रमिक रूप से विकसित करते हुए फसल उत्पादन के लिये उपयोग में लाने की रणनीति अपनाई गई है।

यद्यपि समय–समय पर अनियमित वर्षा से फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथापि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कृषि विकास के संबंध में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार हुआ है तथा वर्ष 2009–10 में गेहूँ के उत्पादन का स्तर 8.45 लाख मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर तक पहुँचा है तथापि मेरी सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि विकास के क्षेत्र में जो नये प्रयास किये गये हैं, उनमें प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी फसलों की बुआई से पूर्व कृषक महोत्सव का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

उक्त के साथ–साथ कृषि विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम को सुदृढ़ बनाया गया है. इसके अंतर्गत सभी अटल आदर्श ग्रामों में कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र खोल दिये गये हैं तथा 52 दूरस्थ अटल आदर्श ग्रामों में कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है. इन केन्द्रों के निर्माण के साथ 147 स्थानों पर कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र सुदृढ़ हो जायेंगे।

प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की बहुलता को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें उचित समय पर सभी कृषि निवेश उपलब्ध हो जाय, यह तभी संभव है जब किसानों को फसली ऋण की उपलब्धता आसानी से हो जाय अतः वर्ष 2010–11 में ही अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की रणनीति तैयार की गयी है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में अटल आदर्श ग्राम के किसानों को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि में लागत तथा श्रम को कम करने तथा विशेष रूप से महिलाओं को अत्यधिक श्रम से मुक्ति दिलाने में कृषि यंत्रीकरण का अत्यधिक महत्व है. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत यंत्र एवं मशीनरी की मांग तो है, किन्तु विक्रेताओं के न होने के कारण यंत्रीकरण के प्रसार को गति नहीं मिल पा रही है. अतः उन्नतशील हल्के टिकाऊ कृषि यंत्र जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उपयोगी हैं. दूरस्थ स्थानों तक न्याय पंचायत स्तरीय कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. इस व्यवस्था का लाभ विशेष रूप से लघु सीमान्त कृषकों एवं महिलाओं को मिलेगा।

आगामी वर्ष के लिये 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्राप्त करने के लिये सभी संभव प्रयास किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म नियोजन के आधार पर विकास की रणनीति को विशेष रूप से अंगीकृत किया गया है. इसके अनुसार चयनित ग्रामों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर उनके पूर्ण विकास हेतु कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा सभी योजनाओं के एकीकृत एवं समन्वित प्रयास से उत्पादन स्तर के नये आयाम प्राप्त किये जायेंगे।

मेरी सरकार के अथक प्रयासों से बीज प्रमाणीकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिससे कृषकों को उन्नतशील और प्रमाणिक बीजों को उपलब्ध कराने में सहायता मिली है।

गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय ने देश की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशुचिकित्सा, प्रौद्योगिकी, मौलिक विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन, वानिकी व मत्स्यकी के क्षेत्रों में उच्चतम शिक्षा, शोध व प्रसार के माध्यम से, देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विकास में विश्वविद्यालय ने विशिष्ट भूमिका निभायी है। इसी कारण मानविकी, गृह विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयों को ISO 2000 का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है।

मेरी सरकार के विशेष प्रयास से शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा देश–विदेश की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के आदान–प्रदान हेतु अनुबंध किये गये हैं जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया एवं हंगरी के शिक्षण संस्थान प्रमुख हैं तथा विश्वविद्यालय को वैश्विक स्वरूप देते हुए इस वर्ष 'इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर' का शुभारम्भ किया गया जिसमें मालदीव देश के विद्यार्थियों के लिए उच्च तकनीक कृषि पर डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा नवीनतम जानकारियों एवं तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी प्रसार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मेरी सरकार कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, सम्पर्क मार्ग योजना, शासकीय प्राथमिक विद्यालय को गोद लिए जाने की योजना तथा बुखारिया योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर रही है।

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि जोत सीमान्त आकार के तथा टुकड़ों में बिखरे हैं। प्रदेश का अधिकांश कृषि क्षेत्र असिंचित है जिसके फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पाद की उपलब्धता मात्र तीन से चार माह के लिएं ही हो पाता है। इसी कारण मेरी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत जलागम विकास योजनायें, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार कर उन्हीं के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिसमें ग्रामीण समुदायों की क्षमता एवं कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जहाँ इन कार्यक्रमों से एक ओर प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आय के संसाधन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि एवं आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद मिल रही है।

(16) उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में गन्ना फसल का कुल क्षेत्र 1.05 लाख हेक्टेयर है। मेरी सरकार ने इसे इस वर्ष बढ़ाये जाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में अवस्थित चीनी मिलों द्वारा गत पेराई सत्र में लगभग तीन सौ अठारह लाख कुन्तल गन्ना पेराई कर आशातीत चीनी में उत्पादन किया है। मेरी सरकार ने सहकारी, सरकारी तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गत पेराई सत्र का सम्पूर्ण देय गन्ना मूल्य भुगतान गन्ना कृषकों को कर दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र के लिए सभी दस चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र हेतु भी गन्ना कृषकों को गन्ने का बेहतर लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार कृत संकल्पित है।

राज्य की चीनी मिलों को घाटे से उबारने हेतु सभी मिलों में चीनी मिल चलाने से पूर्व चीनी मिल की आवश्यक मरम्मत, चीनी परता एवं क्षमता उपयोग बढ़ाने के उपाय, शीघ्र गन्ने ढुलाई के प्रयास, चीनी, शीरा तथा खोई से लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने के नियमित प्रयास कर प्रबन्धकीय एवं वित्तीय सुधार किये जा रहे हैं। साथ ही चीनी मिलों में सह विद्युत परियोजना को पी.पी.पी. मोड में

स्थापित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम चरण में बाजपुर, किच्छा एवं सितारगंज चीनी मिलों में सह विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

गन्ना कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलवाये जाने का प्रयास सरकार कर रही है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों के साथ–साथ प्रदेश के बाहर से प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जा रहा है। गन्ना विकास विभाग, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के सहयोग से गन्ना कृषकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षणों के माध्यम से आधुनिक तकनीक से परिचित करा रहा है।

(17) मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लघु सिंचाई विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त गूल, हाईड्रम योजनाओं की मरम्मत, पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लगभग एक हजार दो सौ योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचन क्षमता का लाभ उठाकर स्थानीय कृषक फल, सब्जी एवं नकदी फसलों का उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ लेने लगे हैं।

मेरी सरकार की महत्वकांक्षी योजना अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य के असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने तथा आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग के वार्षिक बजट में निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

मेरी सरकार ने–

- जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद के अन्तर्गत देहरादून में 7 संख्या, टिहरी में 7 संख्या, उत्तरकाशी में 1 संख्या, हरिद्वार में 5 संख्या, रुद्रप्रयाग में 1 संख्या,

पौड़ी में 7 संख्या अर्थात् कुल 28 संख्या जलाशयों तथा जनपद नैनीताल में 01 संख्या, ऊधमसिंह नगर में 01 संख्या एवं जनपद चम्पावत में 01 संख्या अर्थात् कुल 03 संख्या झीलों व जनपद अल्मोड़ा में 06 संख्या चैक डैम का निर्माण किया गया है;

- इसके अतिरिक्त जलाशयों के निर्माण हेतु अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्यों की 17 संख्या लागत लगभग नौ सौ साठ लाख रुपये एवं जलाशय निर्माण की 28 संख्या लागत लगभग उनतीस सौ चौंतीस लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गयी हैं;
- पर्यटन के दृष्टिकोण से सिंचाई विभाग के विश्राम गृहों को सुसज्जित कर पर्यटकों के उपयोगार्थ तैयार करने पर विचार किया जा रहा है जिससे विश्राम गृहों के समुचित रख–रखाव के साथ राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी;
- छोटी–छोटी नदियों एवं गाड गदेरों को जोड़कर छोटे जलाशय बनाये जाने प्रस्तावित हैं, जिससे भू–जल स्तर में हो रही गिरावट को न्यूनाधिक मात्रा में रोका जा सके;
- पानी की कम उपलब्धता की स्थिति में सिंचाई हेतु अधिकतम उपयोग हेतु ड्रिप/माइक्रो स्प्रिंकलर योजनाओं के निर्माण पर बल दिये जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अन्तर्गत स्प्रिंकलर प्रणाली पर आधारित नलकूपों के निर्माण किये जा रहे हैं;
- सिंचाई योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाने पर बल दिया जा रहा है जिससे सिंचाई, बिजली, पर्यटक स्थलों का विकास, मत्स्य पालन एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सके;
- सिंचाई हेतु निर्मित जलाशयों में नौका विहार, मत्स्य पालन एवं सिंचाई विभाग की भूमि से पार्किंग शुल्क आदि लेकर राजस्व में वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है;
- विभाग को आराकोट–त्यूनी एवं त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आवंटित हुआ है । त्यूनी–प्लासू जल विद्युत परियोजना की

डी0पी0आर0 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी गयी है एवं आराकोट–त्यूनी जल विद्युत परियोजना की डी0पी0आर0 का कार्य प्रगति पर है;

- अल्मोड़ा शहर एवं इसके समीपवर्ती ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु कोसी नदी में कोसी कस्बे के समीप बैराज के निर्माण हेतु रु0 0.33 करोड़ के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रगति में हैं, जिसे आगामी मार्च तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है;

- जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बैजनाथ झील पर लागत लगभग 12 करोड़ है, निर्माणाधीन है। झील के निर्मित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं सिंचाई सुविधा में अतिरिक्त वृद्धि होगी;

- जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं की अग्रणी भूमिका, तकनीकी क्षमता एवं दक्षता के उपयोग हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम" के गठन की स्वीकृति दी गयी है;

- जमरानी बांध परियोजनां उत्तराखण्ड प्रदेश के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से दस किलो मीटर अपस्ट्रीम में 130.60 मीटर ऊँचा आर0सी0सी0 बांध का निर्माण गोला नदी पर प्रस्तावित है । वर्ष 2005 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की लागत रु0 927.93 करोड़ है । वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सहमति प्रदान कर दी गयी है;

- सौंग बांध परियोजना देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 25 कि0मी0 दूर देहरादून टिहरी जिले की सीमा पर स्थित गांव सौंधना (माल देवता) के पास सौंग नदी पर बनाना प्रस्तावित है। बांध स्थल पर पानी की उपलब्धता की गणना के अनुसार देहरादून व समीपवर्ती क्षेत्रों की 2051 तथा आगे तक पेयजल हेतु प्रतिवर्ष/प्रतिदिन उपरोक्तानुसार पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा सिंचाई हेतु भी वर्तमान व्यवस्था को चलाया जा सकेगा। प्रस्तावित बांध लगभग 148.25 मीटर ऊंचा होगा। बांध द्वारा गढ़वाल जल

संस्थान, देहरादून को पानी सप्लाई से पूर्व 6.0 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिनके द्वारा प्रदेश में विद्युत उत्पादन में 38.33 ग 10^6 KWH की प्रतिवर्ष वृद्धि होगी और प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग नौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उपरोक्त परियोजना के निर्माण पर वर्ष 2006 के मूल्यांकन पर पांच सौ चौंतीस करोड़ रुपये (जलापूर्ति प्रणाली को छोड़कर) खर्च आने का अनुमान है।

(18) **मेरी सरकार ने लोकायुक्त संगठन को कर्नाटक लोकायुक्त एवं मध्य प्रदेश लोकायुक्त** की तरह सुदृढ़ एवं अधिक प्रभावी बनाने हेतु कई प्रभावी कदम उठाने का **निश्चय** किया है। इनसे जनमानस को अपेक्षाकृत अधिक राहत प्राप्त होगी **तथा साथ** ही शासन की छवि में भी निखार आयेगा।

(19) **मेरी सरकार ने–**

- **दिनांक 31 मार्च 2010 तक 2149 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 1853** किलो **मीटर** राज्य मार्ग, 650 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग, 6900 किलोमीटर अन्य जिला मार्ग, 19985 किलोमीटर ग्रामीण मोटर मार्ग तथा 1101 किलोमीटर ग्रामीण हल्का वाहन मार्ग इस प्रकार कुल 32638 किलोमीटर मार्ग विभिन्न विभागों के माध्यम से निर्मित किया है।

- एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार प्रस्तावित किया है।

- अटल आदर्श ग्राम सड़क योजना में 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को चयनित किया गया है। इसमें से 570 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को पूर्व में मार्गों से जोड़ा जा चुका है। शेष 100 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को जोड़ने का कार्य प्रगति में है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में प्रत्येक न्याय पंचायत में अधिकतम आबादी वाले असंयोजित गावों को चिन्हित कर मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

- लोक निर्माण विभाग द्वारा गतवर्ष से वर्ष 2019–20 तक हरिद्वार तथा देहरादून शहर में रिंग रोड का निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 72 के किलोमीटर 145 में आई0एम0ए0 के सामने चार लेन भूमिगत मार्ग तथा महत्वपूर्ण राज्य मार्गों/राष्ट्रीय राज मार्गों में ऊपरगामी सेतुओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(20) **मेरी सरकार ने अधिनियम के अनुरूप मादक पदार्थों का आयात, निर्यात,** परिवहन तथा उसे कब्जे में रखने सम्बन्धी कार्यों को विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे राज्य को लगभग डेढ़ करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही देश की विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने में भी सफल रही है।

मेरी सरकार ने मदिरा व्यवसाय पर बड़े ठेकेदारों के एकाधिकार को समाप्त करने एवं नये उद्यमियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश करने के समान अवसर हेतु लाटरी के माध्यम से फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम0आर0पी0 (अधिकतम विक्रय मूल्य) का प्राविधान आबकारी नीति में किया है।

मेरी सरकार ने देशी/विदेशी मदिरा के व्यवस्थापन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों, लॉटरी की प्रक्रिया, राजस्व जमा प्रक्रिया व बिक्री/स्टॉक के ऑन लाईन अपडेटिंग हेतु पीपीपी मोड में मै0 ई–कनेक्ट को अधिकृत किया है। यह कार्य द्रुत गति से प्रगति पर है।

(21) **मेरी सरकार महिलाओं एवं बालकों के कुपोषण स्तर को कम करने, स्कूल** पूर्व शिक्षा से बच्चों को जोड़ने तथा महिलाओं तथा किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधायें उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाने हेतु प्रयासरत है। उत्तराखण्ड की मातृ शक्ति एवं बाल शक्ति को सुरक्षा, संरक्षण एवं समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग" तथा "प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड" की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण तृतीय के आंकडों के आधार पर बच्चों में कुपोषण की समस्या को एक गम्भीर चुनौती मानते हुए राज्य में एक वृहद कुपोषण अनुश्रवण अभियान चलाया जा रहा है जिसमें समस्त बच्चों के पोषण स्तर को सूचीबद्ध करते हुए चिन्हांकित कुपोषित बच्चों को आवश्यक चिकित्सा एवं मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण को प्रतिबद्ध उत्तराखण्ड सरकार द्वारा महिला विकास–परक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु "राज्य मिशन प्राधिकरण" का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त "घरेलू हिंसा अधिनियम" दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन निवारण समितियों के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के लिये सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण में घरेलू हिंसा को 108 सेवा से जोडा है, जिससे महिलाओं को संरक्षण मिला है।

(22) मेरी सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार लगभग अठानवे प्रतिशत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए हैं, जो स्वयं में एक उपलब्धि है।

(23) जनता को सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु राज्य की विभिन्न तहसीलों में नये न्यायालयों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इन न्यायालयों हेतु भवनों/भूमि की व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील प्रताप नगर में सिविल जज, अवर वर्ग खण्ड के न्यायालय की स्थापना सम्बन्धी शासनादेश/अधिसूचना जारी कर दी गयी है एवं जिला देहरादून की तहसील विकासनगर एवं ऋषिकेश में एक–एक अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के गठन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। जिसके सम्बन्ध में शीघ्र शासनादेश जारी कर दिया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में जिला न्यायालय परिसर रुद्रपुर में श्रेणी–एक, दो तथा तीन एवं सिविल जज न्यायालय, विकासनगर में श्रेणी–चार, के आवासों के निर्माण

हेतु एवं जिला देहरादून में ऋषिकेश स्थित न्यायालय भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त न्यायालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में द्वितीय चरण के कार्यों के लिये भी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जिला नैनीताल में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

(24) मेरी सरकार क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ठोस पहल कर रही है और विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

(25) उत्तराखण्ड भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय राज्य होने के कारण राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार एवं ऋषिकेश राज्य में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के पर्यटन स्थल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यात्रियों को सुलभ, आरामदायक एवं दुर्घटना रहित यातायात के साधन उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

मेरी सरकार ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, त्रुटि रहित एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं एन0आई0सी0 के संयुक्त तत्वाधान में तैयार किये गये सॉफ्टवेयर ''वाहन'' (वाहनों के पंजीयन) एवं ''सारथी'' (चालक लाईसेन्स) के आधार पर राज्य के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत ''सड़क दुर्घटना राहत निधि'' का गठन किया गया है।

राज्य में सड़क परिवहन के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हरबर्टपुर, सितारगंज, गदरपुर एवं बागेश्वर में बस अड्डे, स्टैण्ड, स्टेशन एवं डिपो निर्माण/पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है।

यात्रियों को नगर परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं नगर यातायात को जनता के लिये सुलभ एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से आगामी

वित्तीय वर्ष में देहरादून एवं हल्द्वानी नगरों हेतु मोबिलिटी प्लान तैयार कराये जाने का संकल्प किया है।

रक्षाबन्धन पर्व में उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाली बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी।

मेरी सरकार के अथक प्रयास से पन्तनगर हवाई अड्डे का रनवे ए0टी0आर0 टाइप के सभी वायुयानों की लैंडिंग एवं टेक ऑफ हेतु उपलब्ध हो गया है। निकट भविष्य में इस हवाई अड्डे से भी नियमित उड़ानें किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा 'हैली टूरिज्म' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून शहर में सहस्त्रधारा बाईपास रोड पर सम्पूर्ण सुविधाओं के साथ हैंगर एवं हैलीपैड का निर्माण कराया गया है। इस हैलीड्रोम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के लिये हेली सेवाओं का परिचालन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने में सहायता होगी। इसके साथ ही राज्य में पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित स्टेट इनक्लोजर पर बड़े कामर्शियल वायुयानों के अनुरक्षण कार्य सम्पादन हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हैंगर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में एअर कनेक्टिविटी के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है। इस सम्बन्ध में बिड डाक्यूमेन्ट तैयार किया गया है। यू0आई0पी0सी0 के सहयोग से योजना की रूप–रेखा निर्धारित की जानी प्रस्तावित है।

(26) कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय उत्तराखण्ड राज्य के लोगों का परम्परागत व्यवसाय होने के साथ–साथ आजीविका का मुख्य साधन है। मेरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है, कि प्रदेश में पशु सम्पदा व कुक्कुट सम्पदा का विकास इस दृष्टि से किया जाय कि उनकी उत्पादक क्षमता में अभिवृद्धि हो।

मेरी सरकार ने–

- कृषक महोत्सव के माध्यम से राज्य की समस्त न्याय पंचायतों में विभागीय कार्यक्रमों की समग्र जानकारी प्रदान करते हुए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चूजा/चारा बीज, जड़/फीड ब्लाक/चाटन भेली आदि का वितरण किया है,
- भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, कालसी में वर्ष 2010–11 में वर्तमान तक प्राप्त 34 भ्रूणों में से 27 भ्रूण प्रत्यारोपित,
- गौ तथा गौवंश के संरक्षण परिरक्षण हेतु गौ सेवा आयोग की स्थापना।

मत्स्य पालन की दृष्टि से मूल्यवान जल सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस जल सम्पदा में मत्स्य विकास कर इसका समुचित उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं समृद्धि के सशक्त साधनों में एक है, मत्स्य विकास एवं उत्पादन से ग्रामीण अंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा सकता है। अतः मेरी सरकार ने–

- मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान के लिए आवासीय सुविधा के साथ–साथ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।
- राज्य के प्राकृतिक जलस्रोत नदियों, झीलों आदि में मछली के निरन्तर हो रहे ह्रास को रोकने एवं जल प्रदूषण व पारिस्थितिकीय असन्तुलन की रोकथाम आदि हेतु प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्य संरक्षण एव संवर्द्धन की योजना लागू की गई है।

मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना, दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न तकनीकी निवेश सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा नगरीय उपभोक्ताओं हेतु उचित दर पर स्वच्छ दूध एवं दुग्ध पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इस क्रम में दुग्धशाला का क्षमता विस्तार, सहकारी डेरी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, विभिन्न दुग्धशालाओं में प्लान्ट मशीनरी स्थापना तथा प्रबन्धकीय एवं

यातायात अनुदान उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के सहयोग से संचालित डेरी एन्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेन्ट स्कीम को प्रदेश में बिग डेरी के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 25 प्रतिशत अनुदान पर दो से दस दुधारू पशु क्रय हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को योजना अन्तर्गत लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित कर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों से दूध के अतिरिक्त गौमूत्र क्रय कर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

(27) उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार पेयजल विहीन बस्तियों को वायुमण्डल की नमी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयोग करेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दो हजार बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है, ग्रामीण क्षेत्र की बारह सौ योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णोद्धार एवं नगरीय क्षेत्र में एक शहर में आंशिक पेयजल तथा सात शहरों में आंशिक जलोत्सारण व्यवस्था का प्राविधान भी रखा गया है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत बाईस करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है, जिसके अन्तर्गत लगभग अस्सी हजार व्यक्तिगत शौचालय लगाने का प्राविधान भी रखा गया है। विश्व बैंक

सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के लिये भी पर्याप्त बजट का प्रस्ताव किया है।

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु देहरादून एवं नैनीताल शहरों की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। इसी कार्यक्रम के उपमिशन यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0 के अन्तर्गत मसूरी की सीवरेज व्यवस्था हेतु भी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है।

पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव, केन्द्र पोषित गंगा कार्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा द्वितीय चरण, गंगा कार्य योजना अतिरिक्त में सम्मिलित उत्तराखण्ड के दस नगरों के लिये तथा राष्ट्रीय गंगा बेसिन अथोरटी के अन्तर्गत भी बजट प्राविधान रखा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रदेश के इकत्तीस नगरों में पेयजल/जलोत्सारण व्यवस्थाओं की अवस्थापना/विकास हेतु चयनित किया गया है। प्रथम चरण में क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में उपरोक्त व्यवस्थाओं में सुधार हेतु ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार के मध्य श्रण अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है।

(28) मेरी सरकार गत वार्षिक योजना हेतु छः हजार आठ सौ करोड़ का परिव्यय भारत सरकार से अनुमोदित कराने में सफल रही जो कि वर्ष के परिव्यय से एक हजार करोड़ अधिक है।

जिला योजना की धनराशि जिलाधिकारियों/आयुक्तों के निवर्तन पर रखे जाने से जिला योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति में उल्लेखनीय वृद्धि कराने में सफल रही है।

राज्य में प्रथमवार निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक करोड़ से पांच करोड़ तक की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण/जाँच कार्य वरिष्ठ सेवानिवृत्त अभियन्ताओं के पैनल के माध्यम से तथा पांच करोड़ से अधिक लागत

की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण/जाँच कार्य चयनित वाह्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना प्रारम्भ कराने में सफल रही।

पी0पी0पी0 मोड से छः परियोजना प्रारम्भ करने और छब्बीस परियोजनायें प्रगति पर रखने में सफल रही।

मेरी सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तर पर पैंसठ मदों के अन्तर्गत एक सौ पचास से अधिक उपमदों का भौतिक अनुश्रवण कर रही है। इन कार्यक्रमों के कई मदों का अनुश्रवण अन्तर्राष्ट्रीय मंच के यू0 एन0 मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल्स तथा सार्क सोशल चार्टर के अनुरूप पुनः संरचित किया गया है। इस कार्यक्रम में गरीबी हटाने, उत्पादकता बढाने, आय सम्बन्धी असमानताओं को कम करने तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया है।

मेरी सरकार टिहरी झील के आर–पार आने–जाने हेतु पुरानी टिहरी भूकम्प वेधशाला से मदननेगी, सॉंदणा तक लगभग नौ सौ पचास मीटर लम्बे रज्जु मार्ग का निर्माण कराने में सफल रही है।

मेरी सरकार ने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र की यथास्थिति के अभिलेखीकरण हेतु वीडियो डाक्यूमेंटेशन का कार्य कराया है जो घाटी क्षेत्र में भावी योजनाओं को तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

(29) **मेरी सरकार द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी को एक बड़े** कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्वैच्छिक चकबन्दी के संबंध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव एवं इस संबंध में मा0 कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर तैयार किये जाने, समस्त ग्रामवासियों से इस कार्य हेतु सहभागिता प्राप्त करने एवं ग्रामवार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर प्रधान ग्राम पंचायत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

मेरी सरकार ने राज्य से वर्ग– तीन एवं चार के भूमि के कब्जों के विनियमितीकरण के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसकी संस्तुति के क्रम में जनहित में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था के लिये लगभग चार हजार ग्राम प्रहरियों की तैनाती की है।

मेरी सरकार राजस्व पुलिस एक्ट बना रही है तथा राजस्व पुलिस कर्मचारियों का ढ़ांचा बदल रही है।

(30) मेरी सरकार समय–समय पर राजकीय कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बचनबद्ध है, ताकि कार्य में गुणवत्ता लाई जा सके। इसी क्रम में वर्तमान वर्ष में अध्यतन लगभग तीन सौ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रही है तथा सचिवालय में स्थित लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों की सुविधा के लिए आर0टी0आई0 विण्डो सिस्टम का विकास किया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर इसमें और सुधार किया जा रहा है।

(31) मेरी सरकार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें लाभ दिलाना एवं पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास अपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है जिसका उपयोग हम अपने प्रदेश के विकास के लिये कर रहे हैं। राज्य के विकास के लिये बनी योजनाओं में इन पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कार्यवाही मेरी सरकार कर रही है।

मेरी सरकार ने ब्लॉक प्रतिनिधियों की कार्य कुशलता एवं सक्रियता को बढ़ाने के लिए उन्हें मानदेय देकर एक मूलस्रोत पर कार्य करने का पहला कदम उठाया है। इन ब्लॉक प्रतिनिधियों को पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के कल्याणार्थ कार्य करने हेतु मोबाईल फोन भी उपलब्ध कराया गया है इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए निदेशालय एवं सभी जिला

सैनिक कल्याण कार्यालयों में टोल फ्री टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है जिससे पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों की अपनी समस्याओं के संबंध में निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों से निःशुल्क बातचीत कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

मेरी सरकार ने राज्य में चौबीस सैनिक विश्राम गृह संचालित किए हैं। इसके अलावा राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, देहरादून, जिला स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, रुद्रपुर तथा तहसील स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, ऋषिकेश का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है इसके अतिरिक्त तीन सैनिक विश्राम गृह (रुद्रप्रयाग, चौखुटिया एवं मुन्सयारी) निर्माणाधीन हैं एवं कीर्ति नगर, जमणीखाल, घनसाली, विकास नगर, ऊखीमठ एवं थलीसैण सैनिक विश्राम गृह के लिए भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

मेरी सरकार ने अद्यतन तकरीबन नौ हजार पाँच सौ पूर्व सैनिकों तथा सैनिक आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसमें विशेषतः तीन सौ इक्यानवें वीर नारियां और सैनिक आश्रित महिलायें शामिल हैं। मेरी सरकार सिंगरौली, मध्य प्रदेश, गांधीनगर, गुजरात, दार्जिलिंग, सिलिगुड़ी और चौबीस परगना पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली राज्य में भी इन सैनिकों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग दे रही है।

(32) मेरी सरकार 750 ग्राम पंचायतों एवं 10 क्षेत्र पंचायतों में भारत सरकार के सहयोग से खेल मैदानों का निर्माण कराना प्रस्तावित किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर खिलाडियों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

लगभग तीन हजार प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में रिक्त पदो के सापेक्ष तैनात कर रोजगार उपलब्ध कराया है।

- क्षेत्र युवक समितियों तथा जिला युवक समितियों को प्रथम बार मानदेय दे रही है।
- पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों, ब्लॉक कमाण्डर एवं हल्का सरदारों का मानदेय बढ़ाया गया।

- महिला संगठिका का मानदेय बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाडियों को प्रथम बार नकद पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था की है।

मेरी सरकार द्वारा विभिन्न खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत राज्य में ग्यारह स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित तथा चार निर्माणाधीन हैं, दो तरणताल निर्मित हैं, आठ इंडोरहॉल निर्मित एवं दो निर्माणाधीन हैं। विशेष प्रशिक्षण शिविर योजना के अन्तर्गत देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तथा पिथौरागढ़, देहरादून, कोटद्वार एवं हल्द्वानी में बालकों का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) में बालिका आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इन छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, प्रशिक्षण, शिक्षण, किट एवं चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करायी जा रही हैं।

मेरी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में देहरादून एवं औली (चमोली) में आयोजित होने वाले साऊथ एशियन विंटर गेम्स के लिए एक करोड रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। हल्द्वानी (नैनीताल) में अन्तर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त स्टेडियम के डिजाइन एवं डी0पी0आर0 गठित करने हेतु पचास लाख रुपये की धनराशि गत वित्तीय वर्ष अवमुक्त की गयी। जी0आई0 एण्ड टी0आई0, श्रीनगर मैदान एवं पौड़ी के रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

(33) मेरी सरकार शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू0आई0जी0) छोटे एवं मझौले शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0) बेसिक सर्विसेज अर्बन पुअर (बी0एस0यू0पी0) इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (आई0एच0एस0डी0पी0) चला रही है।

मेरी सरकार ने–

- मुख्यत: स्वच्छता, ड्रेनेज, वर्षा जल दोहन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था तथा अन्य अवस्थापकीय सुविधाओं के विकास द्वारा नगरीय क्षेत्रों के विकास,
- पर्यावरणीय स्वच्छता को प्रोत्साहन,
- शहरों तथा विशेषकर पर्यटन एवं धार्मिक महत्व वाले शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु पार्किंग की व्यवस्था;
- स्थानीय निकायों के प्रशासन/कार्यप्रणाली में सुधार लाना ताकि नए कार्यक्रमों के संचालन हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा बाजार से पूंजी प्राप्ति में निकाय सक्षम हो सके; और
- चौहत्तरवें संविधान संशोधन में अपेक्षित सुधारों को लागू करने पर विचार कर रही है।

मेरी सरकार प0 दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग एवं वायबिलिटी गैप योजनान्तर्गत निकाय की आय में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत पी0पी0पी0 मोड/वायबिलिटी गैप फण्डिंग के तहत पार्किंग, शापिंग काम्प्लेक्स, पार्कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, स्लाटर हाऊस, सामुदायिक भवन/ऑडिटोरियम, टाऊन हाल के साथ–साथ ऐसी परियोजनायें जो स्थानीय भौगोलिक एवं जनसुविधाओं के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यकीय हो को वित्त पोषित करने का प्रयास कर रही है।

(34) मेरी सरकार ने मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्तुति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थाओं में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करना, बाल/बंधुवा श्रम की सामाजिक बुराई की रोकथाम की दिशा में प्रभावी ढंग से लागू करना, महिला श्रमिकों को शोषण से बचाना, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सम्बन्धित स्रोतों से सुझाव आमंत्रित कर श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा के कानूनों को युक्त संगत और सरल बनाना तथा निरीक्षण

व्यवस्था को सुखकर एवं पारदर्शी बनाने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ संगठित/असंगठित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एवं श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वयन करने की दिशा में भी मेरी सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

मेरी सरकार ने–

- प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया है।
- प्रदेश में बंधुवा श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया है।
- चीनी मिलों के श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का गठन किया गया है।

मेरी सरकार ने श्रमिकों के हितार्थ–

- योजना विस्तारीकरण के अन्तर्गत खटीमा, किच्छा एवं सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) क्षेत्र में एवं जनपद नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में नये औषधालय स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद देहरादून के तरला-नागल क्षेत्र में 1.154 हेक्टेयर भूमि पर योजना के डाईग्नोस्टिक सेन्टर स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में योजना के औषधालय एवं स्थानीय कार्यालय हेतु 01 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।
- जनपद देहरादून के ग्राम सुद्धोवाला में 08 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालय, निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय व आवासीय परिसर स्थापित किये जाने हेतु भूमि प्राप्ति की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।
- जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि पर चिकित्सालय निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

- प्रदेश में कर्मचारी जीवन बीमा निगम के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु 25 एकड़ भूमि प्राप्ति की कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को नियोजित ढंग से रोजगार देने के नित–नित नये प्रयास कर रही है। बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित करने की दिशा में भी मेरी सरकार ने ठोस पहल की है।

मेरी सरकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के माध्यम से युवक एवं युवतियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न रोजगार परक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वतः रोजगार हेतु दक्ष बनाने की दिशा में कार्य कर रही है तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एप्रेन्टिस स्कीम) के माध्यम से औद्योगिक विकास के अनुरूप तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ मुख्य–मुख्य संस्थानों में प्लेसमेन्ट सैल भी गठित कर चुकी है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रमों के सुधार एवं आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि तथा वर्तमान में औद्योगिक समूहों की अपेक्षानुसार औद्योगिकीकरण एवं रोजगार परक दृष्टि से उपयोगी व्यवसायों का सृजन भी मेरी सरकार द्वारा किया गया है।

(35) मेरी सरकार ने पत्रकारों की सुविधाओं के दृष्टिगत मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान कराई है। इसी प्रकार परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा पत्रकार संगठनों को समय–समय पर आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों के लिए विभाग द्वारा सहायता भी प्रदान की जा रही है।

मीडिया हितों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही लघु एवं मझोले समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पर्याप्त विज्ञापन जारी किये जाने का कार्य भी मेरी सरकार कर रही है।

मेरी सरकार की सक्रियता के फलस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य को प्राप्त सफलता के कारण ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्वस्तरीय कम्पनियाँ और संस्थायें राज्य में निवेश करने हेतु आकर्षित हुई हैं। इस सफलता से राज्य के नवयुवकों को रोजगार के नवीन साधन उपलब्ध हो रहे हैं।

मेरी सरकार स्वान, नेशनल ई–गवर्नेन्स, कॉमन सर्विस सेण्टर, स्टेट डाटा सेण्टर, ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, मिशन मोड परियोजना पर भारत सरकार के सहयोग से उत्कृष्ट कार्य कर रही है।

(36) मेरी सरकार विद्युत की माँग एवं आपूर्ति को कम करने के दृष्टिगत गैस आधारित विद्युत परियोजना की नीति बनाने पर कार्यवाही कर रही है। इसमें निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विद्युत गृह लगाये जाने का प्रस्ताव है।

मेरी सरकार विभिन्न क्षमता के परिवर्तकों की अर्थिंग, एल0टी0 लाईनों का सुदृढ़ीकरण, कृषि पोषकों के पृथकीकरण के कार्यों को प्राथमिकता पर कर रही है। विद्युत चोरी को रोकने हेतु एल0टी0 कन्डक्टर को एरियल बन्च कन्डक्टर (ए0बी0सी0) से बदलने का कार्य विद्युत चोरी प्रभावित क्षेत्रो में कर रही है, जिससे कि विद्युत चोरी पर अंकुश लग सकेगा।

(37) मेरी सरकार शासन तथा प्रशासन में स्वच्छ छवि देने में सफल रही है। इस दिशा में ठोस प्रयास करते हुए सतर्कता अधिष्ठान को सुदृढ़ किया गया है। इससे भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

(38) मेरी सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रचार–प्रसार एवं जागरूक किये जाने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के महत्व एवं वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए गठन किया है।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मेरी सरकार ने ठोस पहल करते हुए राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का गठन किया है।

मेरी सरकार ने –

- राज्य डिजिटल डाटाबेस सृजन कार्यक्रम के तहत भू उपयोग, परती भूमि, मृदा, भूजल संभाव्यता, भूगर्भ, भू–अपरदन आदि सत्रह बहुविषयक मानचित्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है, साथ ही रेखीय विभागों के उपयोगार्थ वेब आधारित सूचनातंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- जल संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत केन्द्र द्वारा इसरो के सहयोग से ''भूजल संभाव्यता मानचित्रों'' का निर्माण कर रेखीय विभागों को सौंप दिया है।

- हिमनद प्राधिकरण के गठन के अंतर्गत समस्त प्रदेश के हिमनदों का मानचित्रीकरण कर सूचीबद्ध किया है। जलवायु परिवर्तन के समग्र अध्ययन हेतु केन्द्र द्वारा प्रदेश की उच्च हिमालयी क्षेत्र में वृक्ष पंक्ति पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन कर एटलस का निर्माण किया गया है। बर्फ एवं हिमनद प्राधिकरण का गठन भी मेरी सरकार द्वारा किया गया।

(39) मेरी सरकार ने–

- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में पहली बार ट्रैफिक लाईट्स के क्षेत्र में देहरादून शहर में तेरह स्थानों में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के आधार पर सोलर आधारित एल0ई0डी0 ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगाये जाने का कार्य किये जाने का संकल्प किया है।

- इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1, हरिद्वार के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के नब्बे आवासीय भवनों का निर्माण करा रही है एवं भल्ला कॉलेज के निकट हरिद्वार नगर पालिका परिषद् की भूमि पर लगभग पैंसठ लाख की लागत से टाऊन हॉल का निर्माण कार्य किया है। इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–दो के अन्तर्गत डुप्लैक्स भवन, ग्रुप हाऊसिंग के अन्तर्गत मल्टीस्टोरी

भवन, हैल्थ क्लब, फुटकर दुकानों आदि का निर्माण कार्य किया जाना भी प्रस्तावित है।

- नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल झील व जनपद की चार अन्य झीलों के सुधारीकरण, संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण से सम्बन्धित योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसमें नैनीताल की झील के लिये 'लेक वार्डन प्रोजेक्ट' नाम की एक योजना तैयार की गयी है।

(40) **मेरी सरकार द्वारा पर्यटन नीति के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के** अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है जिससे उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके।

मेरी सरकार–

- हरिद्वार में धोबीघाट पार्किंग का विस्तारीकरण,
- हरिद्वार में पन्तद्वीप घाट का विकास,
- स्वर्गाश्रम में रामझूला से परमार्थ निकेतन तक गंगा नदी के बायें तट पर घाटों का नवीनीकरण एवं निर्माण, तथा
- स्वर्गाश्रम में वेद निकेतन घाट का निर्माण करा रही है।

मेरी सरकार राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण–सम्वर्द्धन एवं उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा इनका प्रचार–प्रसार, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण तथा

इनका अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण तथा उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक/सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कराए जा रहे हैं।

मेरी सरकार ने लुप्त हो रही लोक संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु गुरु–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत मूर्धन्य गुरुओं के मार्गदर्शन में लोक संगीत की प्रदेश के छः जनपदों में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं तथा प्रदेश में लुप्त हो रही बादी संस्कृति के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के उद्देश्य से इस संस्कृति के पन्द्रह प्रतिभागियों/कलाकारों की कार्यशाला का आयोजन किया है। लोक कलाकारों को चरणबद्ध रूप में वाद्य यंत्र एवं वेश–भूषा क्रय कर उपलब्ध करायी जा रही है।

मेरी सरकार ने मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियाँ धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती, ऐसे साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को उनकी कृतियों के प्रकाशनार्थ लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना स्वीकृत की गई है।

मेरी सरकार ने लोक संस्कृति/लोक कलाओं एवं सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखे जाने तथा इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रेक्षागृहों का निर्माण कर रही है।

(41) मेरी सरकार ने–

- चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड निवास को ध्वस्त कर नये उत्तराखण्ड भवन बनाये जाने का निर्णय लिया है।
- मसूरी में अतिथि गृह के निर्माणार्थ भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु शासन द्वारा रु0 616.15 लाख की धनराशि संबंधित संस्था को दिये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त भूमि राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वामित्वाधीन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

• लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं कौसानी (बागेश्वर) स्थित सर्किट हाऊस/निरीक्षण भवन को राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय हो चुका है। वहाँ व्यवस्थाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है तथा हस्तान्तरण एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(42) मेरी सरकार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के फलस्वरूप आस्तियों एवं कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन में नब्बे प्रतिशत तक सफलता प्राप्त कर ली है। शेष अन्तिम आवंटन के लिए भी मेरी सरकार प्रयासरत है।

(43) समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना मेरी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। सरकार दलितों, जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, विकलांगजनों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए बचनबद्ध है और इन वर्गों के कल्याण के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

(44) मेरी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ पहँचाने तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने हेतु प्रयासरत है।

मेरी सरकार ने वाणिज्य कर संग्रह में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं और छोटे व्यापारियों, भट्टा व्यवसायियों, टेंट व्यवसायियों, संविदाकारों तथा रोड साइड ढाबों के लिए समाधान योजना चलाई है। पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों की सहायता की भी व्यवस्था की गई है।

(45) मेरी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विजन 2020 तय किया है जिसके अन्तर्गत हमारा लक्ष्य है कि हम समृद्धशाली, शिक्षित, स्वस्थ्य, सुसंस्कृत तथा हरित उत्तराखण्ड की स्थापना जन सहयोग के माध्यम से करेंगे।

मैंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा है। मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। मैं माननीय सदस्यगण का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ।

जय हिन्द !